भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1966

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन

†1966. श्री गणेश सिंहः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत शहर-वार प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, इसमें कितनी परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, उन पर कितना व्यय हुआ है और शहरी क्षेत्र में इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) राज्य में शेष परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा उनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मोबिलिटी, सार्वजनिक सेवाओं, सुशासन तथा जीवन-स्तर में हुए सुधारों का आकलन करने के लिए कोई परिणाम मूल्यांकन, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अथवा कार्यान्वयन-पश्चात प्रभाव अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सतना में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्या कोई परियोजना संचालित है, यदि कोई हो, तो उनकी परियोजना-वार व्यय स्थिति, वास्तविक प्रगति तथा अपेक्षित परिणाम क्या हैं तथा समयबद्ध कार्यान्वयन, गुणवत्ता मानकों के पालन और सार्वजनिक धन के दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से तंत्र अपनाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में 07 शहरों अर्थात् भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन का चयन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 31.03.2026 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 15,129 करोड़ रुपये की कुल 788 परियोजनाओं में से 14,612 करोड़ रुपये की 778 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 98 प्रतिशत) पूरी की जा चुकी हैं। राज्य 3,430 करोड़ रुपये की अपनी संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा करने में सक्षम है, जिसमें

से 3,422 करोड़ रुपये (99%) का उपयोग किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में दावा की गई और उपयोग की गई परियोजनाओं और केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	शहर का नाम	भारत सरकार की निधि की स्थिति		कुल परियोजनाएं		पूर्ण परियोजनाएं	
		दावा की गई भारत सरकार की निधियाँ	उपयोग की गई भारत सरकार की निधियाँ	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत
1	भोपाल	490	490	82	2,791	82	2,791
2	ग्वालियर	490	490	84	1,633	81	1,416
3	इंदौर	490	490	231	3,751	231	3,751
4	जबलपुर	490	490	130	2,197	130	2,197
5	सागर	490	489	80	1,782	78	1,607
6	सतना	490	483	86	1,363	83	1,262
7	उज्जैन	490	490	95	1,613	93	1,589
	कुल	3,430	3,422	788	15,129	778	14,612

सतना स्मार्ट सिटी द्वारा 31.03.2026 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 1,363 करोड़ रुपये की कुल 86 परियोजनाओं में से 1,262 करोड़ रुपये की 83 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 97%) पूरी की जा चुकी हैं।

नीति आयोग ने सितंबर 2025 में प्रकाशित 'पैकेज 4 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन - शहरी परिवर्तन और कौशल विकास' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि एससीएम राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिक आवश्यकताओं के साथ मजबूत तालमेल सुनिश्चित करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार, मिशन ने 8,063 परियोजनाओं में से 93% की उच्च परियोजना पूर्णता

दर और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) को 100% पूरा करने की उच्च दर प्राप्त की है, जिससे शहरी जीवन अनुकूलता, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में काफी सुधार हुआ है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, सभी 100 स्मार्ट शहरों के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श प्रदान करने तथा सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से 'स्मार्ट सिटी परामर्शिका मंच (एससीएएफ)' के गठन का प्रावधान किया गया है।

*****